विषय-वस्तु

वार्षिक रिपोर्ट 2024–25

1.	**भारत और विश्व—वर्ष 2024–25 में अर्थव्यवस्था**	**1**
1.1	वैश्विक समष्टिगत वित्तीय परिस्थिति	2
1.2	घरेलू समष्टिगत आर्थिक प्रगति	3
1.3	कृषि में सुदृढ़ वृद्धि ने ग्रामीण माँग को बढ़ावा दिया	5
1.4	ग्रामीण आर्थिक गतिविधि जीवंत बनी रही	7
1.5	समष्टिगत आर्थिक दृष्टिकोण	10
	अध्याय 1 का परिशिष्ट	12
2.	**भारत का ग्रामीण एमएसएमई सेक्टर: समावेशी विकास का संवाहक**	**15**
2.1	भूमिका	16
2.2	भारत में एमएसएमई की परिभाषा	16
2.3	भारत के ग्रामीण एमएसएमई	17
2.4	एमएसएमई को सरकार से सहायता	21
2.5	ग्रामीण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता में नाबार्ड की भूमिका	24
2.6	आगे की राह	26
2.7	निष्कर्ष	27
	नोट	27
3.	**एक बेहतर कल में निवेश**	**29**
3.1	जलवायु कार्रवाई	30
3.2	परिदृश्य-आधारित, पुनःसर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम, एलआरईडीपी	34
3.3	पर्यावरणीय दृष्टि से संधारणीय आजीविका के निर्माण के लिए जनजातीय अनुकूलन पहल, ट्राइब्स	40
3.4	भविष्य की दृष्टि	42
	नोट	42
4.	**संधारणीय आजीविकाओं के माध्यम से समावेशी विकास**	**43**
4.1	ग्रामीण सशक्तीकरण हेतु उत्प्रेरक के रूप में सूक्ष्मवित्त	44
4.2	संधारणीय आजीविकाओं हेतु पहलें	45
4.3	कृषक उत्पादक संगठन	47
4.4	ग्रामीण एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण	51
4.5	ग्रामीण उद्यमियों, स्टार्टअपों, विपणन और ब्रांडिंग को सहयोग प्रदान करना	54
4.6	अनुसंधान को बढ़ावा देना और ज्ञान की साझेदारी का संवर्धन	59
4.7	आगे की राह	60
	अध्याय 4 का परिशिष्ट	61
5.	**ग्रामीण आधारभूत संरचना का वित्तपोषण**	**63**
5.1	ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि	65
5.2	ग्रामीण आधारभूत संरचना संवर्धन निधि	69
5.3	दीर्घावधि सिंचाई निधि	70
5.4	सूक्ष्म सिंचाई निधि	71

5.5	नाबार्ड आधारभूत संरचना विकास सहायता	71
5.6	फसलोपरांत आधारभूत संरचना	73
5.7	अन्य आधारभूत संरचना पहलें	78
5.8	आगे की राह	80
नोट		80

6. वित्तीय समावेशन के लिए ऋण की आयोजना और वितरण 81

6.1	ऋण आयोजना	82
6.2	पुनर्वित्त ऋण का स्नैपशॉट	83
6.3	वित्तीय वर्ष 2025 में पुनर्वित्त ऋण में नई पहलें	87
6.4	ऋण विस्तार के अन्य साधन	88
6.5	ऋण वितरण पारिस्थितिकी तंत्र दक्षता में सुधार लाना	91
6.6	वित्तीय समावेशन बढ़ाना	93
6.7	आगे की राह	95
नोट		96

7. नाबार्ड की पर्यवेक्षी भूमिका 97

7.1	नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षित संस्थाएँ	98
7.2	वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान पर्यवेक्षण व्यवस्था की प्रमुख घटनाएँ	100
7.3	अन्य पर्यवेक्षी पहलें	101
7.4	सूचना प्रौद्योगिकी और साइबर सुरक्षा से संबंधित पहलें	103
7.5	आगे की राह	104
नोट		104

8. ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को सशक्त बनाना 105

8.1	अल्पावधि सहकारी संस्थाएँ	106
8.2	दीर्घावधि सहकारी संस्थाएँ	108
8.3	अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना की मुख्य बातें	108
8.4	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	111
8.5	आगे की राह	115
अध्याय 8 का परिशिष्ट		117
नोट		120

9. कार्मिक—प्रक्रियाएँ और नीतियाँ 121

9.1	अपने कार्मिकों का संपोषण और सहयोग	122
9.2	जोखिम प्रबंधन और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण	124
9.3	पारदर्शिता और सतर्कता का सुदृढ़ीकरण	126
9.4	संधारणीय डिजिटल आधारभूत संरचना का निर्माण	128
9.5	डेटा प्रबंधन और सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण	130
9.6	संसदीय समिति के दौरे और संसदीय प्रश्न	131
9.7	राजभाषा संवर्धन	131
9.8	विपणन और संचार रणनीति के बीच तालमेल	132
9.9	कार्य परिवेश में सुधार का संवर्धन	132
9.10	भारत के ग्रामीण विकास के लिए एक सक्रिय नाबार्ड	133
नोट		134

10. वित्त के माध्यम से विकास 135

10.1	निधियों के स्रोत	136
10.2	निधियों का उपयोग	138

10.3 आय और व्यय 142
10.4 कृषि और ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र में नाबार्ड का निवेश 143
अध्याय 10 के अनुबंध: वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड की सहायक संस्थाओं का कार्यनिष्पादन 145

कॉर्पोरेट अभिशासन 153

वार्षिक लेखे 2024–25: नाबार्ड का स्टैंडअलोन तुलन-पत्र: लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25 173
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध
अनुसूची 18

वार्षिक लेखे 2024–25: नाबार्ड का समेकित तुलन-पत्र: लाभ और हानि लेखा, और नकदी प्रवाह 2024–25 223
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध
अनुसूची 18

नाबार्ड प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभागों और सहायक संस्थाओं के ई-मेल पते 263

क्षेत्रीय कार्यालय/ कक्ष/ प्रशिक्षण संस्थान/ सहायक संस्थाएँ 264

तालिका

1.1 वैश्विक आर्थिक संकेतक (वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि %) 3
1.2 प्रतिव्यक्ति मासिक उपभोग - व्यय में अनाजों/ खाद्य पदार्थों का हिस्सा 6
अ1.1 कृषि क्षेत्र में रूपांतरकारी नीतिगत परिवर्तन 12

2.1 भारत में एमएसएमई की परिभाषा 17
2.2 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एमएसएमई का श्रेणीवार वितरण (संख्या लाख में) 17
2.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता हेतु नाबार्ड के सहयोग 25

4.1 वित्तीय वर्ष 2025 में स्वयं सहायता समूह - बैंक लिंकेज कार्यक्रम का कार्यनिष्पादन 44
4.4 कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का निधि-वार संवर्धन (राशि ₹ करोड़ में) 47

अ8.1 रास बैंकों और जिमस बैंकों का समेकित प्रदर्शन (राशि ₹ करोड़ में) 117
अ8.2 रासकृग्रावि बैंकों और प्रासकृग्रावि बैंकों की वित्तीय स्थिति का विहंगावलोकन (राशि ₹ करोड़ में) 118
अ8.3 वित्तीय वर्ष 2025 में सीडीएफ़ के तहत निधि का उपयोग 118
अ8.4 क्षेग्रा बैंकों का समेकित कार्यनिष्पादन (राशि ₹ करोड़ में) 119
अ8.5 वित्तीय वर्ष 2025 में क्षेग्रा बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लक्ष्यों के समक्ष उपलब्धि 119

9.1 वित्तीय वर्ष 2025 में आयोजित प्रमुख निगरानी और जवाबदेही बैठकें 126
9.2 वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड से संबंधित संसदीय समितियों के दौरे 131
9.3 प्रगति 1.0 की प्रमुख उपलब्धियाँ 133

10.1 नाबार्ड के रणनीतिक निवेश और प्रतिलाभ 144

चित्र

1.1 प्रमुख समष्टिगत आर्थिक रुझान 4
1.2 कृषि और संबद्ध क्षेत्र जीवीए, खाद्यान्न, और बागवानी उत्पादन वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (%) 5

1.3	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक खाद्य मुद्रास्फीति	6
1.4	कृषि हेतु ऋण प्रवाह	7
1.5	2024-25 में ग्रामीण उपभोग माँग	8
1.6	ग्रामीण परिवारों की प्रवृत्तियाँ - आय और रोज़गार (अगली तिमाही में प्रत्याशित परिवर्तन)	8
1.7	ग्रामीण गतिविधि संकेतक (विव 2024 की तुलना में विव 2025 के औसत मूल्यों में % परिवर्तन)	9
1.8	ग्रामीण आर्थिक गतिविधि का मिश्रित संकेतक (मार्च 2025)	10
3.1	निधि के प्रकार के अनुसार जलवायु परिवर्तन पहलें	31
3.2	केएफ़डबल्यू मृदा कार्यक्रम के अंतर्गत मृदा के पुनरुद्धार की पहल	36
4.1	कौशल विकास और उद्यमिता विकास कार्यक्रम (31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार)	45
4.2	विव 2025 तक कृषक उत्पादक संगठनों का संवर्धन (मुख्य बातें)	48
4.3	जीवीएन के तहत सहयोग	52
4.4	31 मार्च 2025 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआईसी को नाबार्ड का सहयोग	55
4.5	विपणन पहलों की प्रगति	56
5.1	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण भारत हेतु नाबार्ड द्वारा प्रबंधित आधारभूत संरचना निधियाँ	64
5.2	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	65
5.3	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आरआईडीएफ के अंतर्गत उपलब्धियाँ और परिणाम	66
5.4	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एलटीआईएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	70
5.5	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एमआईएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	71
5.6	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नीडा के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	72
5.7	नीडा के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं के संभावित परिणाम	73
5.8	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भंडारागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत मंजूरी और संवितरण	74
5.9	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डब्ल्यूआईएफ के अंतर्गत क्षेत्र-वार कार्यनिष्पादन	74
5.10	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार भांडागार आधारभूत संरचना निधि के अंतर्गत उपलब्धियाँ	75
5.11	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार नाबार्ड द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत संरचना	76
5.12	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार डीआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	78
5.13	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एफआईडीएफ के अंतर्गत कार्यनिष्पादन	79
6.1	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार एजेंसियों द्वारा कृषि के लिए आधार स्तरीय ऋण (अनंतिम आंकड़े)	83
6.2	दीर्घावधि और अल्पावधि पुनर्वित्त सहायता	84
6.3	एजेंसियों द्वारा अल्पावधि पुनर्वित्त का संवितरण	85
6.4	अल्पावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा	85
6.5	दीर्घावधि पुनर्वित्त का एजेंसी-वार संवितरण	86
6.6	दीर्घावधि पुनर्वित्त का क्षेत्र-वार संवितरण और हिस्सा	87
6.7	वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान विशेष पुनर्वित्त योजनाओं और नए पुनर्वित्त उत्पादों का कार्यनिष्पादन	89
6.8	वितीय वर्ष 2025 में अन्य ऋण उत्पादों का कार्यनिष्पादन	90
7.1	ग्रामीण संस्थागत ऋण संरचना (31 मार्च 2025 की स्थिति में)	98
7.2	वित्तीय वर्ष 2025 में नाबार्ड द्वारा पर्यवेक्षण	99
7.3	वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान की गई प्रवर्तन कार्रवाइयाँ	103
8.1	वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में रास बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)	107
8.2	वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2024 में जिमस बैंकों का कार्यनिष्पादन (₹ '000 करोड़ में)	107

8.3	31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार क्षेत्रा बैंकों का नेटवर्क	111
8.4	वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 तक क्षेत्रा बैंकों के कार्यनिष्पादन की मुख्य बातें	112
8.5	क्षेत्रा बैंकों का समामेलन, चरण IV नाबार्ड की भूमिका	113
9.1	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार स्टाफ संघटन	122
9.2	वित्तीय वर्ष 2025 में प्रशिक्षण संबंधी उपलब्धियाँ	123
10.1	निधियों के स्रोत (राशि ₹ करोड़ में)	137
10.2	निधियों का उपयोग (राशि ₹ में)	139
10.3	पुनर्वित्त के माध्यम से आधार स्तरीय ऋण का सुदृढ़ीकरण 31 मार्च 2025 तक की स्थिति	140
10.4	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार आधारभूत संरचना वित्त	141
10.5	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार सामाजिक क्षेत्र निवेश	141
10.6	दिनांक 31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार अधिशेष निधियों का निवेश	142
10.7	आय विश्लेषण	142
10.8	नाबार्ड की सहायक कंपनियों में शेयरधारिता (₹ करोड़ में)	143

बॉक्स

अ1.1	केंद्रीय बजट वित्तीय वर्ष 2026 में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए घोषित उपायों की मुख्य बातें	13
3.1	परिदृश्य-आधारित पुन:सर्जक, अनुकूलनक्षम, वर्षा-आधारित पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एलआरईडीपी) की प्रमुख विशेषताएँ	35
3.2	अतिदोहित ब्लॉकों/ वाटरशेडों में सहभागितामूलक संधारणीय भूमिगत जल प्रबंधन	35
3.3	तमिलनाडु के कोट्टेरी वाटरशेड में जल बजट पर प्रकरण अध्ययन	37
3.4	जीवा के माध्यम से कृषि-पारिस्थितिकीय रूपांतरण का विस्तार	40
3.5	जनजातीय विकास निधि 31 मार्च 2025 तक उपलब्धियाँ और परिणाम	41
4.1	एफपीओ क्रेडिट लीग 2025	47
अ4.1	ग्रामीण भारत महोत्सव	61
9.1	'रिस्क मैटर्स!' - जोखिम जागरूकता माह फरवरी 2025	125
9.2	सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024	127
9.3	नाबार्ड को आईएसओ 27001:2022 प्रमाणन प्रदत्त	129
अ10.1	लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई देशों में लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र विकास परियोजना	148

शोकेस

3.1	समुदाय-संचालित आजीविका विकास के माध्यम से तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली	31
3.2	झरनों के जल तक पहुँच के माध्यम से खेती का विस्तार	38
3.3	पतरातू, झारखंड में प्राकृतिक खेती का परिवर्तनकारी प्रभाव	39
3.4	पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में ट्राइब्स के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल आजीविका का निर्माण	42
4.1	हरियाणा के हिसार और सिरसा जिलों में नवोन्मेषी आईओटी-आधारित झींगा पालन पर प्रायोगिक परियोजना	49
4.2	चन्नपटना लाखवेयर हस्तशिल्प के माध्यम से आजीविका में वृद्धि - एक जीआई-आधारित कृषीतर विकास संगठन सफलता की कहानी	52
4.3	एमएबीआईएफ - उद्भवन और उद्यम विकास के माध्यम से ग्रामीण नवोन्मेषन का संवर्धन	54

4.4	'स्टॉल इन मॉल' - शहरी स्थानों की शोभा बढ़ाते ग्रामीण नवोन्मेष	57
4.5	विरासत का परचम लहराया - जीआई पंजीकरण के माध्यम से त्रिपुरा पचरा को मिली स्थानीय विरासत से राष्ट्रीय पहचान	58
5.1	तमिलनाडु राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करना	67
5.2	केरल में संधारणीय विकास और महिला सशक्तीकरण हेतु आँगनवाड़ियों के लिए सौर ऊर्जा	69
5.3	उत्तर प्रदेश के औरैया में ग्रामीण गोदाम आधारभूत संरचना के माध्यम से खाद्यान्न भंडारण और किसानों की अनुकूलन क्षमता में वृद्धि	75
5.4	असम में आधुनिक चावल मिल की स्थापना	77
6.1	मेघालय में ग्रामीण बैंकिंग एजेंटों का सशक्तीकरण	94